Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Need to improve digital platform for online education in Jharkhand-laid

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): नीति आयोग की शिक्षा रैंकिंग के अनुसार मेरा गृह-राज्य झारखंड बड़े राज्यों में सबसे नीचे अंकित 5 नामों में एक है, और वृद्धिशील प्रगति के मामले में सबसे पीछे है । यह शोचनीय विषय है कि झारखंड में केवल 30% बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 70% है । कोविड-19 महामारी ने शिक्षा प्रणाली को हिला कर रख दिया है । झारखंड, जो पहले से ही खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, यहाँ स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है । बिना आवश्यक बुनियादी ढांचे के ऑनलाइन शिक्षा ने राज्य में परिस्थितियों को और भी निराशाजनक बना दिया है और लोगों तक शिक्षा-स्रोतों की पहुंच को कम कर दिया है । कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा में झारखंड बड़े राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पर है । राज्य में खराब डिजिटल बुनियादी ढांचे के कारण, राज्य दीक्षा और ई-पाठशाला जैसे केंद्रीय कार्यक्रमों के लाभों को जनता तक पहुँचाने में असमर्थ रहा है । इंटरनेट कनेक्शन के बिना ऑनलाइन शिक्षा संभव नहीं है । कहने को तो झारखंड के लगभग 80% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर हैं किन्तु केवल 30% के पास ही इंटरनेट की सुविधा है । ऐसी खराब कनेक्टिविटी के कारण, अधिकांश स्कूलों में शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर हैं । रिपोर्टों के अनुसार, झारखंड में केवल 15.3% स्कूली छात्रों के पास कोविड लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध थे । झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के उचित प्रबंधन के अभाव के कारण लाखों छात्रों का नुकसान हुआ है । पूरी संभावना है कि इसका प्रभाव उनके जीवन में बहुत व्यापक हो और एक पूरी पीढ़ी सीमित अवसरों के साथ बड़ी हो । केंद्र सरकार के निवेदन करता हूँ कि झारखंड राज्य शिक्षा के प्रति सजग हो और वह देश के भविष्य की रक्षा के लिए प्राथमिकता से काम करे, इस हेतु केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश झारखंड राज्य सरकार को दिये जाएँ ।